(b) if so, whether it is a fact that the existing prater sharing agreement is going to expire on 31st May, this.year;

(c) whether the Bangladesh Govern- „ment has sent notes and proposed meet' f"ings of the Indo-BangladesTi Joint Rivers Coirunission before the expiry of the present Memorandum of Understanding; and

(d) if so,, what is Government's re- ,action. tihefreito?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) They fado-Bangladesh Memorandum of Understanding of November, 1985 *inter (ilia* provides, for shar-. - ing of the Ganga Waters at Farakka during the three dry seasons, i. e., 1st January to 31st May of the years 1986,, 1987 and 1988. The question of further sharing arrangements would arise only from 1st January, 1989 onwards.

825. *[Transferred to the 9th May* 1988.]

**गंगा कार्य योजना की प्रगति**

826. श्री राम नरेश यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इसके मुख्य-मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने और उसके निष्कर्षों को सभा पटल पर रखने का विचार रखती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जेड० आर० अन्सारी) :

(क) 31 मार्च, 1988 तक 216.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 205 स्कीमें मंजूर की गई हैं। सभी संस्वीकृत स्कीमों में कार्य प्रगति पर है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान गंगा कार्य योजना का कुल परिव्यय 240 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 1988 तक 75.31 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अभी तक 4.81 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 15 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) गंगा कार्य योजना "जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड" द्वारा प्रदूषण स्रोतों पर पहले किए गए व्यापक अध्ययन पर आधारित है। अध्ययन के अनुसार नदी के किनारे बसे श्रेणी–I के नगरों के सारे अनुपचारित मल जल की नदी में प्रवाहित होना प्रदूषण का मुख्य कारण है। दिसंबर, 1984 में पर्यावरण विभाग द्वारा तैयार की गई गंगा कार्य योजना में व्यवस्था की गई है कि नदी में प्रतिदिन प्रवाहित होने वाले 90 करोड़ लीटर अनुपचारित मलजल का अवरोधन और दिशा-परिवर्तन करके इस प्रदूषण को रोका जाए। यद्यपि कार्य योजना में सम्मिलित स्कीमों का केन्द्र-बिन्दु इसी प्रदूषण का निवारण है परन्तु नदी के जल की गुणवत्ता की व्यवस्थित निगरानी का एक अलग कार्यक्रम शुरू किया गया है जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ नदी जल में भारी धातुओं और अवशिष्ट कीटनाशकों की निगरानी भी कर रहा है। जल गुणवत्ता के प्रबोधन के इस कार्यक्रम द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से गंगा कार्य योजना की स्कीमों के जल गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।